Krishi Kumbh
Online E-Magazine
Www.KrishiKumbh.Com

कृषि कुंभ

E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 05 भाग 05, (अक्टूबर, 2025)
पृष्ठ संख्या 12–15

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता की भूमिका

डॉ. गिरीश गोयल[1] एवं डॉ. संजय सिंह[2]

[1]सहायक निदेशक–शोध, शोध निदेशालय,
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
कुमारगंज अयोध्या

[2]महा निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् लखनऊ,
उत्तर प्रदेश, भारत।

Email Id: – drroyal09@gmail.com

परिचय

भारत की आर्थिक संरचना में ग्रामीण क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग 65 से 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और स्वरोजगार है। ग्रामीण समाज के दो प्रमुख घटक, पुरुष और महिला, समान रूप से भागीदारी निभाएँ तो ग्रामीण विकास संभव है। लंबे समय तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को सिर्फ घरेलू काम और कृषि सहायक तक सीमित माना गया था, लेकिन 21वीं सदी में यह परंपरागत धारणा बदल रही है।

शिक्षा, कौशल, स्व–सहायता समूहों, माइक्रोफाइनेंस योजनाओं और सरकारी प्रोत्साहन आज ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाते हैं। वे केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर रही हैं, बल्कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रोजगार पैदा कर रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं।

महिला उद्यमिता की अवधारणा

व्यवसाय में जोखिम उठाकर नवीन विचारों को बदलकर आर्थिक मूल्य बनाना उद्यमिता है। यह पद एक महिला को "महिला उद्यमी" कहा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता का मतलब सिर्फ व्यवसाय चलाना नहीं हैय यह परिवार, समाज और स्थानीय अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व भी करती है। ग्रामीण महिला उद्यमी कृषि–आधारित कार्यों में शामिल हैं, जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई–बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्योग।

ग्रामीण महिला उद्यमिता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत की ग्रामीण महिलाएँ पारंपरिक रूप से आर्थिक क्षेत्र में काम करती रही हैं, चाहे वह पशुपालन, बीज संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण या हस्तकला हो। लेकिन लंबे समय तक ये भूमिकाएँ "अनौपचारिक" और "अदृश्य" मानी जाती थीं।

स्वतंत्रता के बाद, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास शुरू हुए,

पंचवर्षीय योजनाओं, महिला विकास कार्यक्रमों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से। 1980 के दशक में स्व–सहायता समूहों की स्थापना ने ग्रामीण महिलाओं को एकजुट किया और उन्हें लघु उद्यमों की शुरुआत करने की प्रेरणा दी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान

कृषि और उससे जुड़े उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल हैं। इन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी 60–80 प्रतिशत है। खेतों में महिलाएँ बोआई, निराई, कटाई, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और सब्जी उगाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

इसके अतिरिक्त, महिलाएँ गैर–कृषि क्षेत्रों (जैसे हस्तकला, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा निर्माण और कुटीर उद्योग) में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। उन्हें सामुदायिक भावना, धैर्य, सृजनशीलता और कार्यकुशलता से सफल उद्यमी बनाया जाता है।

महिला उद्यमिता के प्रमुख क्षेत्र

1. **कृषि आधारित उद्यमिता:** महिलाएँ बीज उत्पादन, जैविक खाद निर्माण, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन और मशरूम उत्पादन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बन रही हैं।
2. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग:** अचार, पापड़, मसाले, सूखे मेवे, जूस, जैम–जेली जैसे उत्पादों का घरेलू स्तर पर निर्माण और विपणन महिलाएँ सफलतापूर्वक कर रही हैं।
3. **हस्तकला और वस्त्र उद्योग:** ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक कला जैसे बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, बांस के उत्पाद, जूट वर्क, हेंडीक्राफ्ट्स आदि का व्यवसायीकरण हो रहा है।
4. **सेवा क्षेत्र:** ब्यूटी पार्लर, डे–केयर सेंटर, टिफिन सर्विस, टेलरिंग, बुटीक और शिक्षा केंद्र जैसी सेवाएँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता का नया आयाम हैं।
5. **पर्यटन और होम–स्टे व्यवसाय:** कुछ राज्यों में महिलाएँ स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य को जोड़कर होम–स्टे व्यवसाय चला रही हैं, जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख घटक

1. **स्व–सहायता समूह:** NABARD और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित SHGs ने महिलाओं को संगठित कर लघु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे वे छोटे उद्योग प्रारंभ कर पा रही हैं।
2. **माइक्रोफाइनेंस और बैंकिंग सुविधा:** ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) और सहकारी संस्थाएँ महिलाओं को आसानी से ऋण प्रदान कर रही हैं।
3. **सरकारी योजनाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम:**
   - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
   - महिला ई–हाट
   - दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
   - स्टार्टअप इंडिया व स्टैंडअप इंडिया
   - महिला कोयर योजना
   - इन योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता के लिए पूंजी, प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान की है।
4. **तकनीकी शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म:** इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार से महिलाएँ ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रचार और ई–कॉमर्स से जुड़ रही

हैं, जिससे उनके उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।

ग्रामीण महिला उद्यमिता के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

महिला उद्यमिता का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तनकारी है।

1. **आर्थिक स्वतंत्रता:** महिलाएँ आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार और समाज में निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर रही हैं।
2. **रोजगार सृजन:** एक महिला उद्यमी अपने साथ कई अन्य महिलाओं को भी रोजगार देती है, जिससे सामुदायिक विकास होता है।
3. **गरीबी उन्मूलन:** लघु उद्योगों के माध्यम से आय में वृद्धि से ग्रामीण परिवारों की गरीबी कम होती है।
4. **सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास:** आर्थिक सशक्तिकरण से महिलाओं का आत्मविश्वास और समाज में सम्मान बढ़ा है।
5. **ग्रामीण विकास में योगदान:** महिला उद्यमिता के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का उपयोग, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

महिला उद्यमिता की चुनौतियाँ

1. **सामाजिक रूढ़िवादिता:** ग्रामीण समाज में अभी भी कई क्षेत्रों में यह धारणा है कि व्यवसाय केवल पुरुषों का क्षेत्र है। यह मानसिकता महिलाओं के लिए बाधा बनती है।
2. **पूंजी की कमी:** प्रारंभिक निवेश की कमी और ऋण प्राप्त करने में कठिनाई महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी समस्या है।
3. **शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव:** तकनीकी ज्ञान, मार्केटिंग कौशल और व्यवसाय प्रबंधन की समझ का अभाव उनके विकास में बाधक है।
4. **विपणन और बाजार तक पहुँच:** ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, परिवहन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक सीमित पहुँच के कारण उत्पादों की बिक्री प्रभावित होती है।
5. **पारिवारिक जिम्मेदारियाँ:** गृहकार्य, बच्चों की देखभाल और सामाजिक दायित्वों के कारण महिलाओं के पास उद्यम चलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता।

महिला उद्यमिता के विकास के उपाय

1. **वित्तीय सहायता और माइक्रोफंडिंग:** बैंकों और वित्तीय संस्थानों को महिला उद्यमियों के लिए ब्याज रहित या कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।
2. **व्यवसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रशिक्षण केंद्र और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है।
3. **सहयोगी ढांचा और विपणन नेटवर्क:** SHGs और सहकारी समितियों को उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन में सहयोग देना चाहिए।
4. **डिजिटल शिक्षा और ई–कॉमर्स प्रशिक्षण:** ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सिखाना चाहिए ताकि वे अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें।
5. **नीतिगत समर्थन और सुरक्षा:** सरकार को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति, कर में छूट, बीमा

और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

सफल महिला उद्यमियों के उदाहरण

1. **केरल की 'अम्मा फूड्स' समूहः** स्व–सहायता समूह की महिलाओं ने मसाले और खाद्य उत्पाद तैयार कर स्थानीय ब्रांड बनाया।
2. **उत्तर प्रदेश की 'लक्ष्मी SHG':** महिलाओं ने जूट बैग, अगरबत्ती और बायो–खाद निर्माण कर सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दिया।
3. **राजस्थान की हस्तकला समूहः** ग्रामीण महिलाओं ने बंधेज, लहरिया, ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी पारंपरिक कला को व्यवसाय में बदला और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच बनाई।
4. **पूर्वोत्तर राज्यों की बांस उद्योग की महिलाएँः** स्थानीय संसाधन (बांस) का उपयोग कर उपयोगी और सजावटी वस्तुएँ तैयार कर रही हैं।

महिला उद्यमिता और सतत विकास लक्ष्य

महिला उद्यमिता संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 5 और 8 में आर्थिक विकास और सम्मानजनक कार्य से सीधे जुड़ी हुई है। इन दोनों लक्ष्यों को साकार करने में ग्रामीण महिला उद्यमिता का योगदान मिलता है।

महिला उद्यमी न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, बल्कि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उत्पाद बनाती हैं जो स्थानीय संसाधनों को बचाते हैं।

भविष्य की दिशा

भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य ग्रामीण महिला उद्यमिता में है। शिक्षा, डिजिटल तकनीक और सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार के साथ–साथ महिला उद्यमिता भी तेज होगी।

भविष्य के लिए प्रमुख लक्ष्यः

- स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता शिक्षा को शामिल किया जाए।
- महिला उद्यमशीलता को एकजुट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर बनाए जाएँ।
- महिला उद्योग मेले और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से बनाए जाएंगे।
- स्थानीय कला पर आधारित उद्यमों, जैविक उत्पादों और पर्यावरण–मित्र वस्तुओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

निष्कर्ष

ग्रामीण महिला उद्यमिता एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है, साथ ही एक आर्थिक गतिविधि भी है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, परिवारों की आय बढ़ाता है और ग्रामीण समाज में समानता, सम्मान और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत आज "आत्मनिर्भर भारत" और "वोकल फॉर लोकल" की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें ग्रामीण महिला उद्यमिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार, वित्तीय संस्थाएँ, समाज और स्वयं महिलाएँ एकजुट होकर इस क्रांति को बढ़ावा देने की जरूरत है।

यदि हर गाँव की महिला एक छोटे–छोटे उद्यम की नींव रखें, तो न केवल उनका परिवार सशक्त होगा, बल्कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी नई ऊँचाइयों पर पहुंच जाएगी।